आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 19.06.2026

पहले मुख्य समाचार :–

- उपनल कर्मियों के हित में कैबिनेट का बड़ा फैसला। समान वेतन की कटऑफ तिथि बढ़ने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
- प्रदेश के कुछ ज़िलों में टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव सख्त। एक सप्ताह में शत–प्रतिशत जांच पूरी करने के निर्देश।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने राजनीतिक दलों के साथ एस.आई.आर अभियान की समीक्षा की। बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की करी अपील।
- बागेश्वर में राज्य अतिथि गृह निर्माण की तैयारी तेज, 45 नाली भूमि पर बनने वाली परियोजना की डीपीआर जल्द होगी तैयार।

कैबिनेट निर्णय

प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने की निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर वर्ष 15 अक्टूबर 2024 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल ने बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार उपनल कार्मिकों को 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का लाभ एक मार्च 2026 से प्रभावी रूप से दिया जाएगा।

बैठक में उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक होने के आधार पर राज्य सरकार अब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली–2026 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने चारधाम यात्रा के दौरान संचालित घोड़ा–खच्चरों के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले गौवंश के विकास और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

नाराज़गी / समीक्षा

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य के कुछ ज़िलों में टीबी मुक्त भारत अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन ज़िलों में मरीजों की सामान्य जांच का आकलन 60 प्रतिशत से कम रहा है, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए।

मुख्य सचिव ने अगले एक सप्ताह के भीतर मरीजों की सामान्य जांच का कार्य शत–प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उच्च संवेदनशील और जोखिम वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक स्तर पर अभियान की प्रतिदिन समीक्षा और निगरानी करने तथा कम स्क्रीनिंग वाले ज़िलों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्क्रीनिंग बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में पंजीकरण बढ़ाने, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर पहचान और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मानसून को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों की चिन्हित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम्स में स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा

देहरादून में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। एक रिपोर्ट–

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि शहर में सीवर लाइन, पेयजल लाइन और विद्युत लाइनों के भूमिगत कार्य कटिंग अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों की विस्तृत सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति दी जा सके।

जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को विभिन्न विभागों के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की मैदानी स्थिति के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में मोहब्बेवाला क्षेत्र में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और राइजिंग मेन बिछाने के कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी को वेतन रोकने की चेतावनी दी। दून एनक्लेव एक्सटेंशन क्षेत्र में प्रस्तावित नलकूप निर्माण के लिए 15 दिनों के भीतर भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए।

भंडारी बाग ओवरब्रिज निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अगस्त माह से पहले परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को यातायात सुविधा का लाभ मिल सके।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

एस.आई.आर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान–एस.आई.आर के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों से अभियान में बूथ लेवल अधिकारियों को सहयोग करने की अपील की।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में गणना फार्म वितरण का कार्य 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, जबकि अब तक 20 प्रतिशत गणना फार्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर डिजिटाइजेशन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि 8 जून से शुरू हुए अभियान के तहत बी.एल.ओ के फील्ड सत्यापन में अब तक 76 हजार 754 मतदाता ए.एस.डी श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से इन मतदाताओं को खोजने का प्रयास करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

निर्देश

बागेश्वर में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह निर्माण परियोजना को राज्य सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इस संबंध में सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परियोजना की कार्ययोजना की समीक्षा की गई और अधिकारियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट– डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह बागेश्वर तहसील के ग्राम ठेलापालन में लगभग 45 नाली भूमि पर विकसित किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य पर्वतीय ज़िले में सरकारी कार्यक्रमों, वीआईपी आवागमन और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

बैठक में सचिव ने निर्देश दिए कि डीपीआर तैयार करते समय वर्तमान आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने अतिथि कक्षों, बैठक कक्षों, प्रशासनिक कक्षों तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रावधान करने को कहा। साथ ही भवन को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने और निर्माण कार्य को गुणवत्ता तथा समयबद्धता के साथ पूरा करने पर जोर दिया।

सचिव ने परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, आवश्यक फर्नीचर, विद्युत उपकरणों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को भी डीपीआर में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज डीपीआर के साथ संलग्न किए जाएं, ताकि स्वीकृति प्रक्रिया में विलंब न हो और निर्माण कार्य समय पर शुरू किया जा सके।

आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से सोनिया मिश्रा।

विकास कार्य

कुंभ मेला–2027 की तैयारियों के तहत हरिद्वार में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। मेला क्षेत्र में सड़क, पुल, पार्किंग और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने बैरागीवाला और श्रीयंत्र क्षेत्र का निरीक्षण कर विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय–सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं।

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट–यूजी पुर्नपरीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रकिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाये रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुर्नपरीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये।